Publication	**Dainik Jagran (Rashtriya)**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Ranjana Mishra
Date	29/07/2025	**Page no**	8
CCM	44.41		

The path to a prosperous India

समृद्ध भारत की राह

रंजना मिश्रा

भारत का आत्मा उसके गांवों में बसता है, और इस आत्मा की सामूहिक शक्ति का नाम है 'सहकारिता'। इसका सरल सा अर्थ है- 'मिल-जुलकर अपने विकास के लिए काम करना'। इसी विचार ने गुजरात में अमूल जैसी दूध की क्रांति को जन्म दिया, लिज्जत पापड़ के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और इफको के जरिए करोड़ों किसानों तक खाद पहुंचाई। दशकों से यह सहकारी आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था की एक मूक रीढ़ रहा है। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का अनावरण किया है। इस नीति का सबसे बड़ा जोर व्यवस्था को जमीनी स्तर से, यानी गांव से मजबूत करने पर है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सहकारी समितियां केवल लोकतांत्रिक ही न हों, बल्कि पेशेवर तरीके से चलें।

नीति का एक और क्रांतिकारी पहलू सहकारिता के दायरे का विस्तार करना है। अब सहकारिता सिर्फ खेती-किसानी, दूध या चीनी मिलों तक सीमित नहीं

सरकार यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे

रहेगी। यह नीति पर्यटन, स्वास्थ्य, बीमा, भंडारण, टैक्सी सेवा और यहां तक कि हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों के लिए भी दरवाजे खोलती है। यह नीति ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देती है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह सहकारिता को 21वीं सदी के भारत की जरूरतों के साथ जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए पूंजी यानी धन सबसे जरूरी है। अब तक सहकारी समितियों के लिए पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। यह नीति उन्हें बाजार से भी धन जुटाने के लिए सक्षम बनाएगी। इससे उनकी वित्तीय निर्भरता कम होगी और वे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में ले सकेंगी।

एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस भी बनाया जा रहा है, जो एक ही जगह पर देश की सभी सहकारी समितियों की जानकारी रखेगा। इससे बेहतर योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। यह नीति उस छोटे किसान के लिए है, जो अपनी फसल का सही दाम चाहता है। यह उस महिला के लिए है, जो घर पर रहकर भी सम्मान के साथ आजीविका कमाना चाहती है। यह उस युवा के लिए है, जो अपने गांव में ही रहकर एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता है, लेकिन सिर्फ नीति बना देना ही काफी नहीं होता। इसकी असली सफलता इसके सही और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नीति का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसा होगा तभी यह नीति भारत को सामूहिक प्रयास की शक्ति से एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की राह पर मीलों आगे ले जाएगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

****

Downloaded from
SAMVAD